



अण्डमान निकोबार द्वीप समूह



मसाला महोत्सव : मिट्टी से आत्मा तक—मसाला यात्रा—2025 बुधवार को

इच्छुक व्यक्ति 15 जुलाई, 2025 को शाम 3 बजे तक अपने नाम और विवरण पर्यटन निदेशालय में भेज सकते हैं

श्री विजय पुरम, 14 जुलाई। मेलों, उत्सवों और आयोजनों की चल रही श्रृंखला के अंतर्गत, पर्यटन विभाग 16 जुलाई, 2025 को मसाला महोत्सव—2025 मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका उद्देश्य अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उगाए जाने वाले मसालों के पाककला, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना है, साथ ही आगंतुकों को एक गहन कृषि-पर्यटन अनुभव प्रदान करना है। यह महोत्सव संस्कृति, व्यंजनों और कृषि-आधारित गतिविधियों के जीवंत मिश्रण के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस महोत्सव के एक भाग के रूप में, प्रतिभागी द्वीप समूह के प्रमुख मसाला केंद्रों के निर्देशित पर्यटन पर निकलेंगे। इनमें रंगावांग स्थित पदमश्री कमाची वेल्लम्मल (नारियल अम्मा) के प्रसिद्ध फार्म, सीपीघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र-केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कैडलंगज स्थित जंगली मिर्ची रिजॉर्ट के जैविक फार्म का भ्रमण शामिल है। कार्यक्रम में यात्राक्रम शामिल हैं:

- बागान भ्रमण और मसाला कटाई के अनुभव
- मसाला प्रसंस्करण और पैकेजिंग तकनीकों पर लाइव प्रदर्शन
- पारंपरिक व्यंजनों में स्थानीय रूप से उगाए गए मसालों के उपयोग को प्रदर्शित करने वाले चुनिंदा पाककला सत्र।



प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पर्यटन विभाग ने बुधवार 16 जुलाई, 2025 को उपरोक्त मार्गों के लिए आधे दिन की एक समर्पित बस सेवा की व्यवस्था की है, जो इस निदेशालय से सुबह ठीक 8.30 बजे प्रस्थान करेगी। विभाग पर्यटकों, इच्छुक हितधारकों, टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षुओं और पर्यटन क्षेत्र के छात्रों को द्वीपों की मसाला विरासत का जश्न मनाने और एक स्थायी पर्यटन मॉडल के रूप में कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देने में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है।

इच्छुक व्यक्ति 15 जुलाई, 2025 को शाम 3 बजे तक अपने नाम और विवरण पर्यटन निदेशालय, श्री विजय पुरम के प्रबंधक, मोबाइल-9933255364 पर भेज सकते हैं।

टीबी मुक्त अभियान पर मीडिया कार्यशाला हुई द्वीप समूह सहित सभी जिलों में टीबी मुक्त अभियान को मिशन मोड में लागू करने का निर्देश

श्री विजय पुरम, 14 जुलाई। गत 12 जुलाई, 2025 को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में टीबी मुक्त अभियान पर एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. सुजा एंटनी और राज्य टीबी अधिकारी डॉ. पी. लाल ने मीडिया को संबोधित किया। कार्यशाला में भारत सरकार के निर्देश पर प्रकाश डाला गया, जिसमें द्वीप समूह सहित सभी जिलों में टीबी मुक्त अभियान को मिशन मोड में लागू करने का निर्देश दिया गया है। डॉ. सुजा एंटनी ने अभियान के प्रति उच्च-स्तरीय प्रशासनिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसकी नियमित निगरानी माननीय उप राज्यपाल, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य



सचिव और सभी उपायुक्तों द्वारा की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों और सामुदायिक आउटरीच में गहन जाँच के माध्यम से टीबी का शीघ्र पता लगाना है। कमजोर व्यक्तियों—जैसे टीबी का इतिहास रखने वाले, टीबी रोगियों के निकट संपर्क में रहने वाले, धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले, मधुमेह रोगी, कुपोषित व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और एचआईवी से ग्रस्त व्यक्ति—की सक्रिय रूप से जाँच की जा रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं और जाँच को प्रोत्साहित कर रहे हैं। डॉ. लाल ने अभियान के दोहरे फोकस पर विस्तार से बताया, जो प्रारंभिक पहचान और पोषण संबंधी सहायता से संबंधित है। निक्षय पोषण योजना के तहत, टीबी रोगियों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रति माह 1,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, व्यक्तियों और संगठनों को रोगियों को मासिक भोजन की

वन महोत्सव : बालिका विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम



श्री विजय पुरम, 14 जुलाई। अण्डमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने दक्षिण अण्डमान वन विभाग के सहयोग से आज श्री विजय पुरम स्थित बालिका विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और जीवन को बनाए रखने में वृक्षों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम (वन महोत्सव) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और समुदाय को पर्यावरण की रक्षा, जैव विविधता के संरक्षण, वायु प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में

शिक्षित करना था। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके, आयोजकों ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति साझा जिम्मेदारी की भावना को प्रेरित करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति कौशिक चंदा और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति कृष्णा राव तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के पोर्ट ब्लेयर स्थित सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार श्री राशिद आलम की गरिमामयी उपस्थिति रही। माननीय न्यायाधीशों ने वृक्षारोपण अभियान

सीबीएसई कम्पार्टमेंट / सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 आज से

श्री विजय पुरम, 14 जुलाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कम्पार्टमेंट / सप्लीमेंट्री परीक्षाएँ 2025, इन द्वीपसमूहों में 15 जुलाई, 2025 से शुरू होंगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा 15 जुलाई, 2025 को होगी, जबकि कक्षा 10वीं के छात्रों की परीक्षा 15 जुलाई, 2025 से 22 जुलाई, 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस केंद्र शासित प्रदेश से कक्षा 10वीं और 12वीं में कम्पार्टमेंट और इम्पूवमेंट परीक्षाओं में शामिल होने वाले संभावित छात्रों की कुल संख्या इस प्रकार है:

| कक्षा | कम्पार्टमेंट के लिए | सुधार के लिए | कुल |
|-------|---------------------|--------------|------|
| 10वीं | 261 | 313 | 574 |
| 12वीं | 308 | 371 | 679 |
| कुल | 569 | 684 | 1253 |

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश से एआईएसएससीई (12वीं) और एआईएसएससीई (10वीं) की परीक्षा देने वाले छात्रों की सुविधा के लिए कुल 12 परीक्षा केंद्रों की पहचान की गई है। सीबीएसई ने परीक्षा की गोपनीय सामग्री की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक/पुलिस स्टेशन को भी संरक्षक के रूप में चिन्हित किया है। इन परीक्षाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई, चेन्नई के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा केंद्र अधीक्षकों की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है। परीक्षाओं के सुचारु संचालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं।

गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हेतु भारत के पशुपालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित

श्री विजय पुरम, 14 जुलाई। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हेतु भारत के पशुपालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 9 जुलाई, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें केंद्र सरकार, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, दुग्ध संघों और देश भर के उनके प्रमुख हितधारकों के अधिकारियों ने भाग लिया। अण्डमान तथा निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशक ने किया। भारत सरकार

की पशुपालन एवं डेयरी सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने अपने मुख्य भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि पशुपालन एक नकदी उत्पादक क्षेत्र है जो देश के कुल सकल कृषि मूल्य संवर्धन (जीवीए) में 30.7 प्रतिशत का योगदान देता है। उन्होंने आधुनिक एवं सुदृढ़ पशुपालन के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नवाचार, बेहतर गुणवत्ता और मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यशाला में उत्तरी,

तैगोर कॉलेज में डी.ई.आई.एड. पाठ्यक्रम संशोधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला प्रारंभ

श्री विजय पुरम, 14 जुलाई। श्री विजय पुरम स्थित तैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में, गाराचरामा स्थित डॉ. एस. राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.ई.आई.एड.) पाठ्यक्रम के संशोधन हेतु बहुप्रतीक्षित पाँच दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आज प्रारंभ हुई। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर के शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों और शैक्षिक अधिकारियों ने शिक्षा क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डी.ई.आई.एड. पाठ्यक्रम को उन्नत और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से चर्चा की। उद्घाटन सत्र की शुरुआत एसआईई/डाइट की प्राचार्य श्रीमती संगीता चंद के सौहार्दपूर्ण स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की हार्दिक सराहना की और इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने डी.ई.आई.एड. पाठ्यक्रम को समकालीन शैक्षिक प्रथाओं और राष्ट्रीय मानकों के



अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्ग आइलैंड में लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर

श्री विजय पुरम, 14 जुलाई। समाज के 'पिरामिड के निचले स्तर' के समुदायों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को उनके घरों तक पहुँचाने के प्रयास में, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 11 जुलाई, 2025 को लॉन्ग आइलैंड में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।



नवीनीकरण और नए आवेदन के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति पोर्टल

श्री विजय पुरम 14 जुलाई।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस), पोर्टल अब नवीनीकरण और नए आवेदन 2025-2026 दोनों के लिए खुला है। महत्वपूर्ण समय-सीमाएँ इस प्रकार हैं:

| क्र.सं. | विवरण | अंतिम तिथि |
|---------|--|------------------|
| 1. | नवीनीकरण और नया पंजीकरण 2025-2026 | 31 अगस्त, 2025 |
| 2. | एक बार पंजीकरण (नए छात्रों के लिए) 2025-2026 | 31 अगस्त, 2025 |
| 3. | आईएनओ सत्यापन | 15 सितम्बर, 2025 |
| 4. | डीएनओ सत्यापन | 30 सितम्बर, 2025 |

राज्य शिक्षा संस्थान से प्राप्त विज्ञापित में सभी विद्यालयों के प्रमुखों और संस्थान के नोडल अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे नवीनीकरण और नए पात्र लाभार्थियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया को पहले ही पूरा करने के लिए सूचित करें। कृपया ध्यान दें कि सभी नए आवेदकों के लिए एक बार पंजीकरण अनिवार्य है। चयनित छात्रों की सूची संबंधित विद्यालयों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक सहायता के लिए कृपया मोबाइल नंबर 9474219641 पर एनएमएमएसएस, डीलिंग असिस्टेंट श्री दीपक राम, संकाय, राज्य शिक्षा संस्थान से संपर्क करें।

तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, गरज के साथ तूफान के आसार

श्री विजय पुरम, 14 जुलाई।

निकोबार द्वीप समूह में 15 जुलाई, 2025 को एक या दो स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर की भारी बारिश और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ गरज के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। आपदा प्रबंधन निदेशालय से प्राप्त विज्ञापित में मछुआरों के लिए जारी चेतावनी में कहा गया है कि 17 जुलाई, 2025 से 18 जुलाई, 2025 तक दक्षिण अण्डमान सागर में सतही हवाओं की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचने के साथ तूफान आने की संभावना है, समुद्र की स्थिति खराब रहने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 जुलाई, 2025 से 18 जुलाई, 2025 तक दक्षिण अण्डमान सागर के किनारे समुद्र में न जाएं। यह सलाह दी जाती है कि लहरों के बढ़ने की संभावना है, नावों को अत्यधिक सतर्कता के साथ चलाया जाए, मनोरंजन के दौरान उचित सावधानी बरती जाए।

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्ग आइलैंड

पृष्ठ 1 का शेष

ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. अंकुर बरुआ और मुख्य महाप्रबंधक (केजीबी और एमबीपी)-विभागाध्यक्ष श्री संजीव कुमार गोर्गोई चिकित्सा शिविर के दौरान उपस्थित थे। यह शिविर अपोलो क्लिनिक, श्री विजय पुरम के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसमें लॉन्ग आइलैंड स्थित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रेजिडेंट डॉक्टर और टीम का सहयोग रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रेजिडेंट डॉक्टर से प्राप्त जानकारी के आधार पर, शिविर में परामर्श के लिए सामान्य चिकित्सकों के अलावा मेडिसिन, हड्डी रोग और ईएनटी विशेषज्ञ भी उपलब्ध थे। प्राप्त विज्ञापित के अनुसार शिविर के दौरान बुनियादी जाँच की गई, जबकि प्रयोगशाला में विशिष्ट जाँचों के लिए नमूने भी एकत्र किए गए, जिनके परिणाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रेजिडेंट डॉक्टर के माध्यम से मरीजों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए साझा किए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 100 लोगों ने भाग लिया।

टैगोर कॉलेज में डी.ई.आई.एड. पाठ्यक्रम संशोधन

पृष्ठ 1 का शेष

पाठ्यक्रम में नवीन शिक्षण पद्धतियों, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्थानीय संदर्भिकरण और समावेशी शिक्षा रणनीतियों को शामिल करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में, शिक्षा निदेशालय में कार्यालय प्रमुख श्री ज्ञानशील दुबे ने एक विचारोत्तेजक मुख्य भाषण दिया। उन्होंने भावी शिक्षकों को तैयार करने में डी.ई.आई.एड. पाठ्यक्रम की अपरिहार्य भूमिका पर प्रकाश डाला और कार्यशाला को वर्तमान कमियों को पाटने का एक सामयिक और रणनीतिक प्रयास बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को शिक्षा क्षेत्र के समक्ष आज की उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ संशोधन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

टैगोर कॉलेज की प्राचार्य डॉ. मंजू लता राव ने सम्मानित अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। अपने प्रेरक संबोधन में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डी.ई.आई.एड. पाठ्यक्रम में संशोधन "समय की माँग" है। तेजी से विकसित हो रहे शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षकों की बढ़ती माँगों को देखते हुए, उन्होंने शिक्षक शिक्षा के सभी हितधारकों से सहयोग करने, अंतर्दृष्टि साझा करने और इस महत्वपूर्ण प्रयास में सार्थक योगदान देने का आह्वान किया। कार्यशाला का एक प्रमुख आकर्षण मुख्यभूमि के

प्रतिष्ठित संस्थानों के कई प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की भागीदारी थी। इन विशेषज्ञ वक्ताओं में पूर्व संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक), एससीईआरटी, नई दिल्ली डॉ. नाहर सिंह, डाइट, आर.के. पुरम, नई दिल्ली के प्राचार्य डॉ. दिनेश कुमार, एससीईआरटी, नई दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉ. सहारा शर्मा तथा आरआईई, भुवनेश्वर के सहायक प्रोफेसर डॉ. वरुण अशोकन शामिल थे।

प्राप्त विज्ञापित के अनुसार उन्होंने आधुनिक शिक्षण रणनीतियों, पाठ्यक्रम विकास और शिक्षक शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर अपनी विशेषज्ञता साझा की। उनकी अंतर्दृष्टि ने प्रतिभागियों को इस क्षेत्र के नवीनतम रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर बहुमूल्य दृष्टिकोण प्रदान किए। सत्र का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जहाँ आयोजकों ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेषज्ञ वक्ताओं और सभी प्रतिभागियों को उनके अमूल्य योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। कार्यशाला के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने में उनके समर्पित प्रयासों के लिए आयोजन समिति का भी विशेष आभार व्यक्त किया गया।

इस आयोजन ने आने वाले दिनों के लिए एक आशाजनक माहौल तैयार किया और यह आशा भी व्यक्त की कि कार्यशाला के परिणाम पूरे राज्य में शिक्षक शिक्षा में प्रभावशाली और स्थायी सुधार लाएंगे।

गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हेतु भारत के पशुपालन

पृष्ठ 1 का शेष

पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रित चर्चा के लिए चार क्षेत्रीय सत्र शामिल थे। प्रत्येक सत्र में क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों पर सक्रिय रूप से चर्चा की गई, जिसमें उत्पादकता बढ़ाने, बीमारियों पर नियंत्रण

और टिकाऊ पशुधन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। समापन सत्र में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं और सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया।

वन महोत्सव : बालिका विद्यालय में

पृष्ठ 1 का शेष

में सक्रिय रूप से भाग लिया और छात्रों के साथ बातचीत की, तथा टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्या श्रीमती रूपरत्ना ने पुष्पगुच्छ भेंट कर गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत वन महोत्सव के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए एक संबोधन के साथ हुई। माननीय न्यायाधीशों ने स्वयं विद्यालय परिसर में पौधे रोपे और अपने उदाहरणों से छात्रों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों, वन विभाग के अधिकारियों

और विधि सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संसाधन व्यक्तियों ने बताया कि वृक्षारोपण और उनकी देखभाल कैसे मृदा संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और पारिस्थितिक संतुलन में योगदान करती है।

प्राप्त विज्ञापित के अनुसार कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समन्वय और पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार-सह-सदस्य सचिव श्री राशिद आलम ने किया, जिन्होंने सभी हितधारकों के प्रति उनके सक्रिय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए।

द्वीप समूह सहित सभी जिलों में टीबी मुक्त

पृष्ठ 1 का शेष

टोकरी दान करके निक्षय मित्र बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वर्तमान में 200 से अधिक टीबी रोगी इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। 'अनिडको' ने 50 रोगियों को एक वर्ष के लिए 6 लाख रुपये की सहायता देने का संकल्प लिया है। कई सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। प्राप्त विज्ञापित के अनुसार यह अभियान टीबी की

रोकथाम, शीघ्र उपचार और कलंक को कम करने, शिष्टाचार से खांसने, उचित वेंटिलेशन और टीबी निवारक उपचारों की वकालत करने के बारे में जन जागरूकता पर भी जोर देता है। अधिकारियों ने जनभागीदारी और अंतर-विभागीय सहयोग के माध्यम से एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। जनता से इस मिशन में शामिल होने और टीबी रोगियों की सहायता करने का आग्रह किया गया है, जिससे द्वीप समूह को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य में योगदान मिल सके।

मोटर थर्ड पार्टी बीमा की अनिवार्य आवश्यकता के लिए निर्देश जारी

श्री विजय पुरम, 14 जुलाई।

वाहन मालिकों का ध्यान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति, यात्री के रूप में छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, वाहन के उपयोग के संबंध में इस अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू न हो।"

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोटर थर्ड पार्टी बीमा की अनिवार्य आवश्यकता के लिए निर्देश जारी किए हैं और पाया है कि सड़कों पर चलने वाले बिना बीमा

वाले वाहन दुर्घटनाओं या क्षति के मामले में मालिकों और तीसरे पक्ष के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

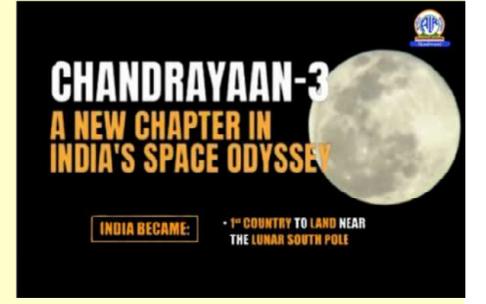
प्राप्त विज्ञापित के अनुसार एमवी अधिनियम की धारा 196 में यह प्रावधान है कि "जो कोई भी धारा 146 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाता है या चलाने की अनुमति देता है, उसे निम्नलिखित दंड दिया जाएगा: पहला अपराध: 3 महीने तक कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना या बाद का अपराध: 3 महीने तक कारावास या 4000 रुपये का जुर्माना या दोनों।

उपरोक्त के मद्देनजर, आम जनता को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों का बीमा कवर सुनिश्चित करें, ऐसा न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चंद्रयान-3 ने आज अपने प्रक्षेपण के दो वर्ष पूरे किए

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

भारत के विज्ञान और दृढ़ संकल्प की ऐतिहासिक उपलब्धि, चंद्रयान-3 ने आज अपने प्रक्षेपण के दो वर्ष पूरे कर लिए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट ऊँचाई वाले क्षेत्रों में लैंडर और रोवर को स्थापित करना तथा संपूर्ण लैंडिंग और रोविंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। वर्ष 2023 में आज ही के दिन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो द्वारा विकसित एलवीएम3 एम4 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया था।



आयकर विभाग ने देश भर में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शुरू किया है

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

आयकर विभाग ने देश भर में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयकर रिटर्न में कटौतियों और छूटों के फर्जी दावों को बढ़ावा देने वाले लोगों और संस्थाओं की जांच करना है। इस जांच में कुछ आईटीआर तैयार करने वालों और बिचौलियों द्वारा संचालित संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो फर्जी कटौतियों और छूटों का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल कर रहे थे। विभाग ने कहा है कि इस फर्जी फाइलिंग में लाभकारी

प्रावधानों का दुरुपयोग भी शामिल है और कुछ लोग अत्यधिक रिफंड का दावा करने के लिए झूठे टीडीएस रिटर्न भी दाखिल कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष में विभाग ने संदिग्ध करदाताओं को अपने रिटर्न में संशोधन करने और सही कर का भुगतान करने के लिए एसएमएस और ईमेल के द्वारा परामर्श और व्यापक संपर्क अभियान चलाए हैं। परिणामस्वरूप पिछले चार महीनों में लगभग 40 हजार करदाताओं ने अपने रिटर्न अपडेट किए हैं और स्वेच्छा से एक हजार करोड़ से ज्यादा के झूठे दावे वापस लिए हैं।

आयुष मंत्री ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप आयुर्वेद में भी अनुसंधान को और सशक्त बनाने की ज़रूरत पर बल दिया

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

सुश्रुत जयंती के मौके पर, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली में शल्य तंत्र पर आधारित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन, शल्यकॉन 2025 का उद्घाटन किया। एआईआईए के शल्य तंत्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के सहयोग से आयोजित यह राष्ट्रीय सेमिनार, एनएसए के 25वें वार्षिक सम्मेलन का एक हिस्सा था। इस कार्यक्रम में भारत तथा नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी मुल्कों के विद्वानों, आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और शल्य चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और छात्रों समेत 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए श्री प्रतापराव जाधव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मुताबिक, आयुर्वेद में अनुसंधान को और सशक्त करने की ज़रूरत बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "अनुसंधान को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। गहन वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल के जरिए, हमारी पारंपरिक प्रणालियों के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। भारत सरकार पहले ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों को 39 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और 19 अतिरिक्त ऑपरेशन करने के लिए अधिकृत कर चुकी है, जिससे स्वास्थ्य सेवा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण मजबूत हुआ है।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपचार की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शल्य चिकित्सा प्रोटोकॉल का मानकीकरण ज़रूरी है।

इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय के उप महानिदेशक श्री सत्यजीत पॉल, राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के अध्यक्ष पद्मश्री प्रो. मनोरंजन साहू, एनएसए के सचिव प्रो. पी. हेमंत कुमार, निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. (डॉ.) मंजूषा राजगोपाला भी उपस्थित थीं। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आयुर्वेद और प्रौद्योगिकी के जरिए नवाचार में भारत के सशक्त होते नेतृत्व पर जोर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि सितंबर 2024 में एआईआईए और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक वैश्विक तकनीकी बैठक में, पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक तकनीकी संक्षिप्त विवरण जारी किया गया था। आयुष भी, स्वदेशी चैटबॉट, एकीत आयुष मास्टर एप्लिकेशन और एएचएमआईएस, आयुष ई-एलएमएस, आयुष अनुसंधान पोर्टल और नमस्ते

योग ऐप जैसे 22 से अधिक डिजिटल मंचों जैसे उपायों के साथ एआई अनुप्रयोगों को आगे बढ़ा रहा है। भारत डबल्यूएचओ-आईटीयू एफजीए-आईएचएच पहल में भागीदारी के जरिए वैश्विक एआई शासन में भी योगदान दे रहा है। कार्यक्रम के दौरान 13 और 14 जुलाई को लाइव सर्जिकल प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें 10 लेप्रोस्कोपिक/एंडोस्कोपिक प्रक्रियाएँ और 16 एनोरेक्टल सर्जरी सफलतापूर्वक की गईं। इसके अलावा, शल्य तंत्र में मानकीकरण और नवाचार पर वैज्ञानिक सत्र, पोस्टर प्रस्तुतियों और विशेषज्ञ पैनल चर्चाएँ भी शामिल थे। आयोजन के अध्यक्ष, प्रो. (डॉ.) योगेश बडवे ने बताया कि एआईआईए अब रोजाना 2000 से अधिक रोगियों की सेवा करता है, और इसका शल्य तंत्र विभाग नियमित रूप से सामान्य, लेप्रोस्कोपिक, स्तन, एनोरेक्टल और मूत्र संबंधी सर्जरी करता है। ये विकास रोगी-केंद्रित एकीकृत देखभाल प्रदान करने में आयुर्वेद की प्रसंगिकता को दर्शाती है।

"नवाचार, एकीकरण और प्रेरणा" विषय के साथ, शल्यकॉन 2025 आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ाएगा, जिससे एकीकृत स्वास्थ्य सेवा में भारत के नेतृत्व को बल मिलेगा।

इस प्रतिष्ठित उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुश्रुत सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों के हाथों एक सम्मेलन स्मारिका पुस्तक का विमोचन भी किया गया और एक पीजी सारांश भी प्रस्तुत किया गया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) अपनी तरह का पहला संस्थान है, जिसकी स्थापना एम्स की तर्ज पर की गई है। इसे प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर 2017 को दूसरे आयुर्वेद दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया था। इसका मकसद आयुर्वेद तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए एक उत्कृष्ट उत्कृष्टता केंद्र बनाना और मानवता के हित के लिए आयुर्वेद के जरिए शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के उच्चतम मानक स्थापित करना है। यह एनएबीएच मान्यता प्राप्त तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने, रोगियों की देखभाल के लिए समग्र और एकीकृत नजरिए वाले तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल के रूप में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अपनी अलग पहचान बनाई है।

ई-निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल-1, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, तुशानाबाद की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुमवी टेकेदारों से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.-8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते हैं।

क्र.सं. कार्य का नाम
1 एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी-1/आर आर (सीसीए)/2025-26/54
तुशानाबाद ग्राम पंचायत के अंतर्गत हाबडीपुर वार्ड नं. 02 में गांव की सड़क से वितरण के घर होते हुए तुलसी और रंजीत के घर तक ड्रेन के साथ सी सी फुटपाथ का निर्माण कार्य।
अनुमानित लागत : रु. 7,07,280/-, धरोहर राशि : रु. 14,146/-, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/-, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22/07/2025 के सायं 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट <https://eprocure.andaman.gov.in> से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2025_RDPRI_19184_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल-1,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई-निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल-1, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, कन्यापुरम की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुमवी टेकेदारों से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.-8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते हैं।

क्र.सं. कार्य का नाम
1 एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी-1/आर आर (सीसीए)/2025-26/48
कन्यापुरम ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वार्ड नं. डब्ल्यूजी 01 में मछली बाजार से ट्रामलेन तक कवर स्लैब का नवीनीकरण।
अनुमानित लागत : रु. 6,56,630/-, धरोहर राशि : रु. 13,133/-, कार्य समाप्ति की अवधि : (03) तीन माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/-, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 22/07/2025 के सायं 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट <https://eprocure.andaman.gov.in> से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2025_RDPRI_19182_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल-1,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई-निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल-1, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, फरारगंज की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुमवी टेकेदारों से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.-8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते हैं।

क्र.सं. कार्य का नाम
1 एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी-1/आर आर/2025-26/41
फरारगंज ग्राम पंचायत के अंतर्गत फरारगंज 02 में एनएच 04 से अनिल मंडल के घर होते हुए अशोक मंडल के घर तक सी सी रोड का निर्माण कार्य।
अनुमानित लागत : रु. 7,88,559/-, धरोहर राशि : रु. 15,771/-, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/-, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22/07/2025 के सायं 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट <https://eprocure.andaman.gov.in> से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2025_RDPRI_19173_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल-1,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

बिस्स्टेक पोर्ट सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने कहा—भारत अब वैश्विक सीफेयरिंग ताकत

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ओडिशा के विशाखापत्तनम में आयोजित बिस्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 में भारत की समुद्री प्रगति और क्षेत्रीय सहयोग को नई उंचाई पर पहुंचाने की बात कही।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में साझा समुद्री नियति की दिशा में यह सम्मेलन एक निर्णायक कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'पड़ोसी पहले' नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अपने बिस्स्टेक साझेदारों के साथ मिलकर निर्बाध संपर्क, क्षमता निर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि हाल ही में समुद्री परिवहन सहयोग पर हुआ बिस्स्टेक समझौता एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो व्यापार में सुगमता, बंदरगाह एकीकरण, जहाजों, चालक दल और माल की पारस्परिक मान्यता के लिए रास्ता खोलता है। उन्होंने कहा कि भारत का बंदरगाह अब केवल व्यापार के प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समृद्धि के इंजन बन चुके हैं। सागरमाला, हरित सागर और 'समुद्री अमृत काल: विजन 2047' जैसी योजनाएं इस दिशा में भारत की दीर्घकालिक सोच को दर्शाती हैं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि भारत ने 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' की त्रिस्तरीय रणनीति के माध्यम से बंदरगाह क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि भारत का बासेल टर्नअराउंड टाइम घटकर चार दिन से कम होकर अब एक दिन से भी नीचे आ गया है, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों से बेहतर है। कटेनराइज्ड कार्गो हैंडलिंग में 70 फीसदी की वृद्धि दर्ज



की गई है, जो 2024 में 79 लाख 20 फीट लंबे कंटेनर (टीईयूएस) से बढ़कर 2025 में 1.35 करोड़ टीईयूएस हो गया है।

उन्होंने बताया कि भारत आज दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सीफेयरिंग राष्ट्र है, जो वैश्विक स्तर पर 15 फीसदी योगदान देता है। 2014 में 1.08 लाख सीफेयरर्स की संख्या बढ़कर अब 3.20 लाख हो गई है, जो 200 फीसदी की वृद्धि है। माल ढुलाई क्षमता भी पिछले दशक में दोगुनी होकर 140 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 276.2 करोड़ मीट्रिक टन हो गई है। समुद्री पर्यटन में भी भारत ने 500 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है, जहां क्रूज टूरिज्म 84,000 से बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि तटीय शिपिंग 87 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 165 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जबकि अंतर्देशीय जल परिवहन में माल ढुलाई 2014 में 18 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 140 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जो 700 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है।

भारत के 'दानवीर' जमशेदजी जीजाभाई, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत से मिली थी 'नाइट' और 'बैरोनेट' की उपाधि

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

जमशेदजी जीजाभाई 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय व्यापारी और सामाजिक सुधारक थे, जिन्हें सर जमशेदजी जीजाभाई (प्रथम बैरोनेट) के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने व्यापारिक कौशल और उदार दानशीलता के माध्यम से न केवल अपार धन-संपत्ति अर्जित की, बल्कि समाज के उत्थान के लिए अपने संसाधनों का उपयोग भी किया। वे भारत के पहले बैरोनेट थे, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ने उनकी परोपकारी सेवाओं के लिए 'नाइट' और 'बैरोनेट' की उपाधि से सम्मानित किया था।

15 जुलाई 1783 को मुंबई (पूर्व में बॉम्बे) में एक पारसी परिवार में पैदा हुए जमशेदजी जीजाभाई का जीवन व्यापार, परोपकार और सामाजिक सुधार के कार्यों में लगा रहा। उनके माता-पिता, जीवाजी और बानुबाई, साधारण परिस्थितियों में जीवन यापन करते थे। हालांकि, कम उम्र में ही अनाथ हो जाने के कारण उनकी परवरिश उनके मामा ने की। उन्होंने शिक्षा तो ज्यादा हासिल नहीं की, लेकिन अपने कठिन परिश्रम और बुद्धिमानी से व्यापार की दुनिया में जल्द ही अपनी पकड़ बना ली।

महज 15 साल की उम्र में उनकी व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि जमशेदजी ने अपने व्यापार की शुरुआत कपास और अफीम के निर्यात से की। उन्होंने अपने मामा के साथ मिलकर पूर्वी एशिया, खासकर चीन का दौरा किया। साल 1805 आते-आते उन्होंने खुद की कंपनी भी बना ली और जल्द ही उनकी गिनती बॉम्बे के प्रमुख व्यापारियों में होने लगी। उन्होंने बहुत कम समय में कपास, अफीम, मसाले और अन्य वस्तुओं के व्यापार में विशेषता हासिल कर ली। उनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता ने उन्हें ब्रिटिश और स्थानीय व्यापारियों के बीच पहचान दिलाई।



हालांकि, व्यापार में सफलता के झंडे गाड़ने के साथ-साथ जमशेदजी जीजाभाई ने खुलकर दान भी किया। उन्होंने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण के लिए दान किया। उन्होंने मुंबई में जेजे हॉस्पिटल की स्थापना के लिए एक बड़ा दान दिया। इसके अलावा, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट संस्थान की स्थापना में योगदान दिया। साथ ही उन्होंने पारसी समुदाय और अन्य समुदायों के लिए कई धर्मशालाएं, स्कूल और अनाथालय भी स्थापित किए। उनकी परोपकारिता इतनी व्यापक थी कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवनकाल में लाखों रुपए दान किए, जो उस समय की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी राशि थी।

जमशेदजी जीजाभाई को उनके योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार से कई सम्मान भी प्राप्त हुए। 1842 में उन्हें 'नाइट' की उपाधि दी गई और 1857 में वे भारत के पहले व्यक्ति बने, जिन्हें 'बैरोनेट' की उपाधि मिली। इसके अलावा, उन्हें मुंबई के जस्टिस ऑफ पीस और विधायी परिषद के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। उनके सम्मान में मुंबई में कई सड़कों और संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। जमशेदजी जीजाभाई ने 14 अप्रैल 1859 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है।

हरियाणा और गोवा को मिला नया राज्यपाल

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

सोमवार को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर अशीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल और पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर (डॉ.) बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है।

ये नियुक्तियाँ उस तिथि से प्रभावी होंगी जिस दिन नए नियुक्त व्यक्ति अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार संभालेंगे। ये नियुक्तियाँ दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख संवैधानिक पदों पर फेरबदल का संकेत हैं। आशिम

मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारी के खिलाफ एक सशक्त हथियार के रूप में काम कर रहा है : ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्विकसित गांवश के निर्माण का आह्वान किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एक श्विकसित गांवश वही होगा जहां हर परिवार के पास बुनियादी सुविधाओं वाला एक पक्का घर होगा, वह गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जुड़ा होगा, हर ग्रामीण युवा के पास रोजगार के अवसर होंगे और हर महिला सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी। यह कोई दूर का सपना नहीं बल्कि इसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें नई ऊर्जा, नवीन सोच और गहरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने की आवश्यकता है। श्री पेम्मासानी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि हम केवल योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत की विकास गाथा का अगला अध्याय लिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है।

श्री पेम्मासानी ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण बेरोजगारी और विशेष रूप से कृषि के कमजोर मौसम में होने वाले संकटपूर्ण पलायन के विरुद्ध एक हथियार के रूप में कार्य कर रही है। इसमें 90,000 से 1,00,000 करोड़ रुपये के वार्षिक निवेश के परिणामस्वरूप टिकाऊ और

कुमार घोष, जिन्होंने वरिष्ठ शैक्षणिक पदों पर कार्य किया है और उच्च शिक्षा में अपने प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं, हरियाणा के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करेंगे।

वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, पुष्पति अशोक गजपति राजू, गोवा में कार्यभार संभालेंगे। राजू ने अपने दशकों लंबे राजनीतिक जीवन में आंध्र प्रदेश और केंद्र दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। जम्मू से भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता, लद्दाख में नई दिल्ली की प्रशासनिक उपस्थिति का नया चेहरा बन गए हैं। गुप्ता इससे पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और पीडीपी-भाजपा गठबंधन काल के दौरान उन्हें उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।



उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। प्रतिवर्ष 250 करोड़ से अधिक मानव-दिवस सृजित हुए हैं, 36 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और 15 करोड़ से अधिक श्रमिक इसके लाभार्थी हुए हैं। श्री पेम्मासानी ने वेतन भुगतान के बजाय सार्थक परिसंपत्ति निर्माण, विविध कार्यों को अपनाने और अन्य विकास योजनाओं के साथ उनके अभिसरण तथा कार्य चयन में सामुदायिक भागीदारी का सुझाव दिया है।

श्री पेम्मासानी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उल्लेख करते हुए बताया कि इसकी शुरुआत से कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए 3.22 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाए जा चुके हैं और परिवार वृद्धि तथा ग्रामीण जनसंख्या विस्तार के कारण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण-अनुकूल और क्षेत्र-विशेष निर्माण तकनीकों और लागत-प्रभावी आवास डिजाइनों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया है।

नीति आयोग ने नई दिल्ली में 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' का तीसरा संस्करण लॉन्च किया

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी ने 14 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2025 (अक्टूबर से दिसंबर) की तीसरी तिमाही के लिए 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' पुस्तिका के तीसरे संस्करण का विमोचन किया।

इस तिमाही के लिए भारत की व्यापार स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, इस संस्करण का विषयगत खंड अमेरिकी टैरिफ संरचनाओं में हाल के बदलावों पर केंद्रित है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पुनर्गठन और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसके निहितार्थों के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024) में भारत के व्यापार निष्पादन ने भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच सतर्क गतिशीलता प्रदर्शित की। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में व्यापारिक निर्यात 3 प्रतिशत (108.7 बिलियन डॉलर तक) बढ़ा, जबकि आयात में 6.5 प्रतिशत (187.5 बिलियन डॉलर तक) की वृद्धि हुई। सेवा निर्यात में 17 प्रतिशत वृद्धि से प्रेरित 52.3 बिलियन डॉलर के सेवा अधिशेष ने घाटे के अंतर को कम करने में मदद की, जिसने वैश्विक सेवा अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती शक्ति को रेखांकित किया। निर्यात संरचना स्थिर बनी हुई है और कुछ उत्पाद जैसे विमान, अंतरिक्ष यान और पुरजे 200 प्रतिशत से अधिक की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ शीर्ष दस निर्यातों में शामिल हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत वर्ष 2024 में 269 बिलियन डॉलर के डिजिटल तरीके से डिलीवर की गई सेवाओं (डीडीएस) के निर्यात के साथ विश्व के पांचवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में स्थान पर रहा।



इस तिमाही के संस्करण का विषयगत केंद्र बिंदु उभरती अमेरिकी व्यापार और टैरिफ संरचनाएं तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके प्रभाव हैं। प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत का सापेक्ष टैरिफ लाभ अमेरिकी बाजार में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और विद्युत मशीनरी जैसे क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का एक कार्यात्मक अवसर प्रदान करता है। उभरते वैश्विक व्यापार परिवेश में नए व्यापार संयोजनों का लाभ उठाने के लिए बेहतर नीति-निर्माण की आवश्यकता है।

इस अवसर पर डॉ. विरमानी ने नवीनतम व्यापार गतिशीलता को गहन विश्लेषणात्मक गहराई के साथ प्रस्तुत करने वाले एक व्यापक व्यापार प्रकाशन के लिए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की उभरती हुई व्यापार भागीदारी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नवोन्मेषण और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के रणनीतिक प्रयासों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था की गहन प्रगति को दर्शाती है, जो अमेरिकी व्यापार नीति में हाल के बदलावों के अनुरूप है।

इतिहास के पन्नों में 15 जुलाई: देश में सबसे पहले मुंबई में चली मोटरबस सेवा

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

देश-दुनिया के इतिहास में 15 जुलाई की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। यह तारीख मुंबई में मोटरबस सेवा के लिए यादगार है। देश में पहली मोटरबस सेवा इसी तारीख को 1926 में चली थी। यह सेवा बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) ने शुरू की थी। पहली बस को अफगान चर्च से क्रॉफोर्ड मार्केट तक चलाया गया था। बेस्ट ने 1934 में मुंबई के उत्तरी हिस्से में अपनी इस सेवा का विस्तार किया। इसके चार साल बाद पहली बार मुंबई में डबल डेकर बस चली।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र— 1904: अमेरिका के लॉस एंजिल्स में पहला बौद्ध मंदिर बना।
1910: एमिल क्रेपलिन ने एलॉइस अल्जाइमर के नाम पर अल्जाइमर बीमारी का नाम दिया।
1916: दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग की शुरुआत।
1926: बॉम्बे (अब मुंबई) में पहली मोटरबस सेवा शुरू।
1955: प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की।
1961: स्पेन ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों को स्वीकार किया।
1968: अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच वाणिज्यिक विमान सेवा की शुरुआत।
1979: भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दिया।



2000: सिएरा लियोन में सैन्य कार्रवाई कर बंधक बनाए गए सभी भारतीय सैनिकों को मुक्त कराया गया।
2002: पाकिस्तान में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख को अदालत ने मौत की सजा सुनाई।
2004: माओवादियों से वार्ता में नेपाल के प्रधानमंत्री ने विदेशी मध्यस्थता मंजूर की।
2005: श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने सुनामी राहत सामग्री बंटवारे विषयक सरकार-लिट्टे समझौते को निलंबित किया।
2008: नेपाल में दोनों प्रमुख वामपंथी दलों के बीच देश के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्तियां और नई सरकार के गठन पर सहमति बनी।
2011: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पीएसऍलवी सी-17 के जरिए जीसैट-12 ए का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण

महज 9 वर्षों में वीजा को पीछे छोड़ यूपीआई बना दुनिया का टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम— संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

नई दिल्ली, 14 जुलाई। भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) अब दुनिया का टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एक्स पर यूपीआई की इस उपलब्धि को एक इंडोग्राफिक के साथ दर्शाया है। उनके द्वारा साझा किए गए यूपीआई आंकड़ों के अनुसार, 650.26 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन काउंट के साथ यूपीआई ने वीजा को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां वीजा के लिए यह आंकड़ा 639 मिलियन दर्ज किया गया है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "भारत का डिजिटल पावरहाउस यूपीआई दुनिया भर में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को लेकर पहले पायदान पर पहुंच चुका है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और परिवर्तनकारी उपलब्धि है।"

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यूपीआई का इस्तेमाल वर्तमान में 7 देशों में होता है, जिनमें सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरीशस शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य देश भी यूपीआई को अपनाने को लेकर साझेदारी आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

इससे पहले नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने यूपीआई की सराहना करते हुए कहा कि यूपीआई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है और इसने नागरिकों के जीवन को

भारत-सऊदी अरब के बीच समझौते, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री

नई दिल्ली, 14 जुलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने 11 से 13 जुलाई 2025 तक सऊदी अरब के दम्माम और रियाद का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच उर्वरक, फार्मा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देना था। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ उर्वरक विभाग और विदेश मंत्रालय के सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।

रियाद में, जे.पी. नड्डा ने सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बंदार बिन इब्राहिम अल खोरेयफ से मुलाकात कर उर्वरकों, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। इस दौरान भारतीय कंपनियों फ्लू, ज़ल्फ्टाह और ब्रू के साथ उर्वरक कंपनी के बीच लंबे समय के लिए समझौते हुए। इन समझौतों के तहत वित्त वर्ष 2025-26 से प्रतिवर्ष 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डाइमोनियम फॉस्फेट उर्वरक की आपूर्ति होगी, जो पांच वर्षों तक चलेगी और आपसी सहमति से पांच और वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है।

दोनों पक्षों ने DAP के साथ-साथ यूरिया जैसे अन्य प्रमुख उर्वरकों पर भी दीर्घकालिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे भारत की उर्वरक सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सऊदी अरब में निवेश के अवसरों और सऊदी निवेशकों को भारत में अवसर देने पर भी चर्चा हुई। साथ ही, भारत-विशिष्ट वैकल्पिक और अनुकूलित उर्वरकों पर संयुक्त शोध को लेकर सहमति बनी।

स्पेस स्टेशन से रवाना हुए शुभांशु शुक्ला, 23 घंटों बाद पृथ्वी पर पहुंचेंगे

वॉशिंगटन, 14 जुलाई। मिशन एक्सओम-4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने अन्य साथियों के साथ स्पेस से धरती के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में कुल 18 दिन बिताए हैं।

अभी तक की जानकारी के अनुसार, स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान की अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और ये यान धरती की ओर रवाना हो चुका है। करीब 23 घंटे बाद ये यान कैलिफोर्निया तट पर उतरेंगा।

जानकारी के अनुसार, गगनयात्री शुभांशु एक्सओम-4 मिशन के अपने तीन सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मंगलवार को प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट पर उतरेंगे। थोड़ी देर पहले ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग हो गई है। अनडॉकिंग के बाद ये स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर

शरपुंखा: पित्त, लिवर और पेट की समस्याओं का प्राकृतिक समाधान

नई दिल्ली, 14 जुलाई। औषधीय गुणों से भरपूर शरपुंखा का वैज्ञानिक नाम 'ट्रेफसिया परचुरिया' है। यह भारत के विभिन्न हिस्सों खासकर सूखे और पथरीले स्थानों पर पाया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर कई स्वास्थ्य संबंधित समस्या से निजात दिलाने के लिए किया जाता है। यह एक छोटा झाड़ीनुमा पौधा होता है, जिसकी ऊंचाई आमतौर पर 30 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी टहनियां अक्सर फैली हुई होती हैं। इसकी पत्तियां हल्की हरे रंग की और छोटी होती हैं, जो बारीक रूप से कटी हुई लगती हैं। वहीं, इसके फूल गुलाबी, बैंगनी या लाल-बैंगनी रंग के होते हैं, और छोटे गुच्छों में खिलते हैं। इसकी एक सफेद फूलों वाली प्रजाति भी होती है। फूल के बाद इसमें छोटी, सीधी फलियां लगती हैं, जिनमें छोटे-छोटे बीज होते हैं।

आयुर्वेद में शरपुंखा को लिवर के स्वास्थ्य के लिए एक लामकारी माना गया है। इसके अलावा, यह जड़ी बूटी पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी है। साथ ही यह खांसी और स्वसन संबंधी जटिलताओं के लिए एक अच्छी मानी गई है। यह लिवर को डिटॉक्स करके विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे लिवर की कार्यक्षमता बेहतर होती है। सरफोका में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इंफेक्शन को दूर करने में मदद करता है। शरपुंखा के फूल को पीसकर उसे शहद में मलिकर चोट या घाव पर लेप को लगाने से घाव जल्दी से ठीक हो जाता है।



बदल दिया है। गौरतलब हो, पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक नोट में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) वेस्ट डिजिटल पेमेंट को व्यापक रूप से अपनाने के कारण भारत अब दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में तेज मुगतान करता है।

यूपीआई की शुरुआत 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा की गई थी, जिसके बाद से ही यूपीआई का तेजी से विकास हुआ है। 'ग्रॉइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स : द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी' शीर्षक वाले नोट के अनुसार, यूपीआई अब प्रति माह 18 अरब से ज्यादा लेनदेन प्रोसेस करता है और भारत में दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पेमेंट सिस्टम पर भी हावी है।

उर्वरक, स्वास्थ्य सहयोग पर की यात्रा से संबंधों को मजबूती



इस दिशा में, भारत की ओर से उर्वरक सचिव और सऊदी अरब की ओर से खनन मामलों के उपमंत्री के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन भी किया गया है, जो दीर्घकालिक साझेदारी के रास्ते तलाशेगी। इसके अलावा, नड्डा ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री और भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी के सह-अध्यक्ष, प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने नड्डा के सम्मान में भोज भी आयोजित किया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई, जब नड्डा ने सऊदी अरब के उप स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल अजीज अल-रुमैह से मुलाकात कर मेडिकल सेवाओं, दवाओं, डिजिटल हेल्थ और ज्ञान-विनिमय पर सहयोग बढ़ाने के विषयों पर बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हालिया सऊदी यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित द्विपक्षीय स्वास्थ्य MoU की उपयोगिता को उजागर किया।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने जैव ईंधन के माध्यम से भारत में एक नई क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की

नई दिल्ली, 14 जुलाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को जैव ईंधन के माध्यम से भारत में एक नई क्रांति लाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप नामीबिया ग्लोबल बायोयूल अलायंस (जीबीए) में शामिल हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि जैव ईंधन एक ऐसी ऊर्जा है जो घरेलू और कृषि अपशिष्ट, अनाज या खराब अनाज से प्राप्त होती है और यह पर्यावरण-अनुकूल, स्वच्छ ईंधन देश के विकास को गति देने का एक सशक्त माध्यम भी है।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नामीबिया जीबीए में शामिल हो गया है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत की पहल और ग्लोबल बायोयूल अलायंस फ़ैमिली का विस्तार, वसुधैव कुटुम्बक के मंत्र पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का एक और प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि जैव ईंधन के प्रति प्रधानमंत्री के प्रयास देश में व्यापक बदलाव ला रहे हैं और नागरिकों के जीवन में सुधार ला रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के प्रयासों ने भारत में 'जैव ईंधन के माध्यम से बदलाव की एक नई क्रांति' ला दी है। भारत की विकास यात्रा को गति देने वाला यह हरित ईंधन गाँवों से लेकर शहरों तक लोगों के जीवन को बदल रहा है और बेहतर बना रहा है। जैव ईंधन न केवल किसानों को आय अर्जित करने में मदद कर रहा है, बल्कि इसके विकास से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर

सांसदों को अटेंडेंस के लिए नहीं लगानी होगी लाइन, लोकसभा में अब सीट पर बैठे-बैठे ऑनलाइन लगेगी हाजिरी

नई दिल्ली, 14 जुलाई। लोक सभा में सांसदों की उपस्थिति अब ऑनलाइन होगी। MMD यानी मल्टी मीडिया डिवाइस के जरिए अब सांसद ऑनलाइन अपनी हाजिरी लगा पाएंगे। नई संसद के बनने से पहले सांसदों को अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए हर रोज अटेंडेंस रजिस्टर में अपने साइन करने होते थे, लेकिन नई संसद में यह प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। सांसदों को टैब में stylus के जरिए लोकसभा और राज्यसभा में घुसने से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती थी। वहीं, अब MMD के जरिए सांसद अपनी एलॉटेड सीट पर बैठकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे।

हालांकि, इस प्रक्रिया में सांसद अपनी एलॉटेड सीट पर बैठकर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे। MMD यानी Multi Media Device के जरिए सांसद थंब इम्प्रेसन, पिन नंबर या मल्टी मीडिया डिवाइस कार्ड के जरिए अब अपनी अटेंडेंस लगा पाएंगे।

पुरानी प्रक्रिया में न सिर्फ ज्यादा समय लगता था, बल्कि कई बार सांसद हस्ताक्षर करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। इसके चलते लोक सभा स्पीकर ने यह पहल शुरू की

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का आदेश: सभी बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच जरूरी

नई दिल्ली, 14 जुलाई। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश में संचालित होने वाली सभी एयरलाइनों, विशेष रूप से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों का उपयोग करने वाली कंपनियों को अपने फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच करने का निर्देश देने की योजना बनाई है।

यह कदम 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में हुई एअर इंडिया विमान की भीषण दुर्घटना पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (एएआइबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है।

उक्त रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच 'रन' से 'कटऑफ' स्थिति (चालू से बंद) में चले गये थे। बहुत संभव है कि इससे ही उक्त दुर्घटना हुई हो।

डीजीसीए के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में जल्द ही एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा जिससे बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच अनिवार्य की जाएगी। वैसे डीजीसीए के इस बारे में फैसला करने से पहले ही एतिहाद और सिंगापुर एयरलाइंस जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने स्वेचिचक तरीके से जांच शुरू कर दी है।

एतिहाद ने 13 जुलाई को अपने बोइंग 787 बड़े के लिए एक इंजीनियरिंग वर्क इंस्ट्रक्शन जारी किया, जिसमें स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच और पायलटों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई। वैसे डीजीसीए ने एयर इंडिया विमान हादसे के

आज से बदलेगा यूट्यूब का नियम, एआई और लो-क्वालिटी कंटेंट वाले क्रिएटर्स की कमाई पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली, 14 जुलाई। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में अपडेट कर रहा है। जो 15 जुलाई 2025 से लागू होगा। इस अपडेट के बाद यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी यानी YouTube Partner Program (YPP) के नियम पहले से ज्यादा सख्त हो जाएंगे। खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जो दोहरावा वाला या एआई की मदद से जनरेट किया गया कंटेंट अपलोड करते हैं, अब उनकी कमाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 15 जुलाई 2025 से यूट्यूब अपने पार्टनर प्रोग्राम रूल को सख्त कर रहा है। नए नियमों के तहत मास प्रोड्यूसर, रिपिटिटर और इनऑर्थेंटिक कंटेंट्स का ऐड रेवेन्यू कम किया जाएगा।

यूट्यूब पर लगातार बढ़ते एआई जनरेटेड और स्पैम कंटेंट की बाढ़ को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिनमें केवल किसी इमेज या वीडियो क्लिप पर एआई वॉइसओवर जोड़ा गया है। इन वीडियोज की गुणवत्ता आमतौर पर कम होती है और इससे असली, क्रिएटिव और ऑर्थेंटिक क्रिएटर्स को नुकसान



पैदा हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ, यह ईंधन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। हाल ही में आईएएनएस के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि इस वर्ष बायोफ्यूल ब्लेंडिंग 20 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो 2014 में मात्र 1.4 प्रतिशत था।

भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, इथेनॉल ब्लेंडिंग पहलों ने पिछले दस वर्षों में किसानों की आय में सुधार किया है। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित हुए हैं, 1.75 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर सीओ२ उत्सर्जन में कमी आई है और 85,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।



है। इसके बाद अब यह MMD सिस्टम इस सत्र से लागू होगा। इसकी शुरुआत लोकसभा से होगी। राज्यसभा में अभी पुरानी प्रक्रिया से ही सांसदों की उपस्थिति दर्ज करवानी होगी।

संसद की कार्यवाही साल में लगभग 70 दिन चलती है, जिसमें हर रोज 2 से तीन मिनट का समय एक सांसद को अपनी उपस्थिति दर्ज करने में लगता है। ऐसे में इस नई प्रक्रिया के तहत सालाना हर सांसद का साढ़े तीन घंटे का समय बचेगा।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का आदेश: सभी बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच जरूरी

नई दिल्ली, 14 जुलाई। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश में संचालित होने वाली सभी एयरलाइनों, विशेष रूप से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों का उपयोग करने वाली कंपनियों को अपने फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच करने का निर्देश देने की योजना बनाई है।

यह कदम 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में हुई एअर इंडिया विमान की भीषण दुर्घटना पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (एएआइबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच 'रन' से 'कटऑफ' स्थिति (चालू से बंद) में चले गये थे। बहुत संभव है कि इससे ही उक्त दुर्घटना हुई हो।

डीजीसीए के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में जल्द ही एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा जिससे बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच अनिवार्य की जाएगी। वैसे डीजीसीए के इस बारे में फैसला करने से पहले ही एतिहाद और सिंगापुर एयरलाइंस जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने स्वेचिचक तरीके से जांच शुरू कर दी है।

एतिहाद ने 13 जुलाई को अपने बोइंग 787 बड़े के लिए एक इंजीनियरिंग वर्क इंस्ट्रक्शन जारी किया, जिसमें स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच और पायलटों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई। वैसे डीजीसीए ने एयर इंडिया विमान हादसे के

बाद बोइंग 787 विमानों की विस्तृत निगरानी पहले ही शुरू कर चुका है, नया निर्देश इस दिशा में एक और कदम होगा। सनद रहे कि एयर इंडिया दुर्घटना पर एएआइबी की रिपोर्ट के बाद वैश्विक उड्डयन सेक्टर में सुरक्षा इंतजामों और खास तौर पर फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर नये सिरे से चर्चा हो रही है। एतिहाद ने अपने एक बोइंग 787 की जांच तब शुरू की, जब वह हैदराबाद के लिए उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद अबू धाबी लौट आया। कंपनी ने बताया कि उसने यह कदम 'अतिरिक्त सावधानी' के तौर पर उठाया है।

सिंगापुर एयरलाइंस ने भी अपने 787 बड़े की जांच शुरू की, जिससे यह संकेत मिलता है कि वैश्विक एयरलाइंस इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं। एएआइबी ने 11-12 जुलाई को आधी रात को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी।

इसमें 17 दिसंबर, 2018 को अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) द्वारा जारी एक स्पेशल एयरवर्थनेस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का उल्लेख किया गया है जिसमें बोइंग 787 सहित कई मॉडलों में फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म में गडबड़ी होने की संभावना को चिन्हित किया गया था। हालांकि इस बुलेटिन को मानने की बाधयता कंपनियों पर नहीं थी। यह सिर्फ सलाह के तौर पर था। दुर्घटनाग्रस्त विमान के काकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) में दर्ज बातचीत में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया, "तुमने फ्यूल क्यों बंद किया?" जिसका जवाब था, "मैंने नहीं किया।"

आपका कंटेंट प्रामाणिक और यूनिक भी होना चाहिए। जो चैनल एआई की मदद से ब्लॉक में कंटेंट बना रहे हैं—जैसे कि फोटो या वीडियो क्लिप पर वॉइसओवर जोड़कर, या इंटरनेट से उठाई गई जानकारी को बिना बदलाव के पेश करके, उन्हें मोनेटाइजेशन से हटाया जा सकता है या उनकी कमाई में भारी गिरावट आ सकती है।

यूट्यूब ने कहा, यह एक छोटा लेकिन जरूरी अपडेट है जिसका उद्देश्य असली और क्वालिटी कंटेंट को बढ़ावा देना है। हम चाहते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे जहां क्रिएटिविटी और मेहनत को पहचान मिले।